पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री और संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) मध्य प्रदेश के सभी 45 जिला मुख्यालयो मे तारघर सुविधा मुहैया करवा दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

नये डाकघर तथा शाखा डाकघरों का खोला जाना

788. **श्री राधा किशन मालवीय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) वर्ष 1990–91 मे कितने नये डाकघर तथा शाखा डाकघर खोले जाने का लक्ष्य निश्चित किया गया है; और

(ख) इन डाकघरो तथा उनके कर्मचारियों पर खर्च की जाने वाली राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री और संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) 1990–91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 1000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 200 विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव था । तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के मानदण्डो को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के सहयोग से संशोधित किया जा रहा है। जब तक मौजूदा प्रक्रिया पूरी नही हो जाती है तब तक राज्यवार डाक नेटवर्क विस्तार कार्यक्रम को अंतिम रूप नही दिया जा सकता है । नए मानदण्ड निर्धारित हो जाने के बाद बजटीय प्रावधानो सहित राज्यवार ब्यौरो को अंतिम रूप दिया जाएगा । सयोग से योजना आयोग ने डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए 1990–91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपए के परिव्यय को अनुमोदित कर दिया है जिसके अन्तर्गत नए डाकघर खोलने का कार्यक्रम भी आ जाता है । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद की रिपोर्ट जनवरी, 1991 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हो जाने की संभावना है।

Procedure for environment clearance

789. SHRI JITENDRABHAI LABHSHANKER BHATT: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have submitted a set of proposals for rationalisation of environment clearance procedures which aim at "expanding the role of the Ministry" as reported in the Deccan Herald of 1st September, 1990, and

(b) if so, the details of improved procedure for environment clearance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) Proposals for rationalisation of environmental impact assessment procedure have been under consideration with the following salient features·—

—Making environmental impact assessment a statutory requirement;

—Uniform coverage of both private as well as public sector projects;

—Delegation of powers for environmental clearance of certain categories of projects to state agencies.

The primary objective of these proposals is to rationalise the procedure rather than expand the role of the Ministry.

मंडल आयोग के प्रतिवेदन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों को हुई क्षति

790. **श्री प्रभाकर राव कलवला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) मंडल आयोग के प्रतिवेदन को लागू करने के विरोध में छात्रो द्वारा किए

गए आन्दोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई दिल्ली परिवहन निगम की बसो की सख्या क्या है ,

(ख) इससे दिल्ली परिवहन निगम को कितने रुपये की हानि हुई; और

(ग) सरकार इस हानि को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है तथा दिल्ली परिवहन निगम को भविष्य मे इस प्रकार की हानि न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार) (श्री मनुभाई कोटाड़िया): (क):मडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के विरोध मे छात्रो द्वारा किए गए आन्दोलन के दौरान लगभग 3290 बसे क्षतिग्रस्त हुई थीं ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के अनुसार इस क्षति के कारण लगभग 1.02 करोड़ रु० का नुकसान हुआ है।

(ग) नुकसान की भरपाई करने के लिये आवश्यक बजटगत सहायता प्रदान करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई है । अगर भविष्य मे कभी भी ऐसे अवसर उत्पन्न हुए तो कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिये कहा जाएगा ।

791. [*Transferred to the 8th Pakistan* 1991]

Views of U.S. Ambassador to Pakistan on Kashmir issue

792. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the reported letter of U.S Ambassador in Pakistan, Mr. Robert Jakely, written recently to Sardar Abdul Qayyum of occupied Kashmir that plebiscite as per U.N. resolution was no longer relevant; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) (a) Government have noted the press reports about the contents of a letter written by the U.S. Ambassador in Pakistan to the so-called President of Pakistan occupied Kashmir, Sardar Abdul Qayyum.

(b) Government have repeatedly reiterated its well-known position that the state of Jammu & Kashmir is an integral part of India.

NRIs returning from the Gulf

793. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of NRIs who have come back from the Gulf in the wake of the crisis there;

(b) what steps have been taken to rehabilitate them; and

(c) the number of those who have been rehabilitated and the place where they are residing, State-wise?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Approximately 1,50,000 Indian nationals, most of whom had non-resident status, have been repartriated from Iraq and Kuwait.

(b) and (c) The evacuees from Iraq and Kuwait have not yet been rehabilitated by the Government.

Projects of Andhra Pradesh pending for environmental clearance

794. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: what are the pending projects proposed by Government of Andhra Pradesh for environmental clearance; since when those are pending and at what stage of consideration these are?